भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1443

12 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः स्वदेशी खाद्यान्नों का मूल्य

1443. श्री मितेष (आनंद) पटेल (बकाभाई)

श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रीअन्न को स्वास्थ्य वर्धक खाद्यान्न के रूप में प्रचारित करने के बावजूद ज्वार, बाजरा और रागी जैसे स्वदेशी खाद्यान्नों की कीमत बहुत अधिक है और यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का ऐसे खाद्यान्नों की कीमत कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईओएम) के रूप मे घोषित किया गया है। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का आयोजन कर रही है ताकि इसे जन आंदोलन बनाया जा सके जिससे कि मूल्य-वर्धित उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता बने। मिलेट्स (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। आईवाईओएम 2023 की कार्य योजना उत्पादन, उत्पादकता, उपभोग, निर्यात को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखलाओं के सुदृढ़ीकरण, ब्रांडिंग तथा स्वास्थ्य लाभों से संबंधित जागरूकता लगने इत्यादि पर भी केंद्रित है।

मोटे अनाजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोषक अनाज (एनएफएसएम-पोषक अनाज) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएफएसएम-पोषक अनाज के तहत शामिल की गई पहलों में प्रथाओं के उन्नत पैकेज पर समूह फ्रंटलाइन प्रदर्शन, बीज वितरण और सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, उच्च उपज गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का उत्पादन, पौध संरक्षण रसायनों, खरपतवारनाशी, स्प्रेयर, कुशल जल उपयोग उपकरण, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं। मिलेट्स के लिए बीज हबों का निर्माण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, पहलों में प्रजनक बीज उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिटों (एचवाईवी) का वितरण इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की शुरुआत की है।

सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने प्रमुख मिलेट्स के लिए एमएसपी का भी निर्धारण किया है ताकि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सके।

मिलेट्स आधारित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जून, 2022 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई है। मिलेट्स को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन के तहत मिलेट्स की खरीद में वृद्धि के लिए इसके संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी मिलेट की खरीद में वृद्धि करने की सलाह दी है।

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के उपरोक्त प्रयासों के कारण मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में जागरूकता बढ़ी है और मिलेट्स की मांग में वृद्धि हुई है। सरकार, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उत्पादन और आपूर्ति बढ़ सके तथा कीमतों को संतुलित रखा जा सके।

*****